नईदुनिया

केंद्रीय बजट 2024 से पहले वित्त मंत्री की मौजूदगी में हलवा समारोह का आयोजन

नई दिल्ली ।

केंद्रीय बजट 2024 के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में वित्त मंत्रालय यानी नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। हलवा समारोह का आयोजन केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में नॉर्थ ब्लॉक में किया गया। बजट तैयार करने की लॉक-इन प्रक्रिया शुरू होने से पहले हर साल एक परंपरा के तहत हलवा समारोह या हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। बजट पेश होने से पहले क्यों होता है हलवा समारोह वित्त मंत्री की ओर से बजट से ठीक पहले एक हलवा समारोह का आयोजन किया जाता है। यह हलवा समारोह इस बात का परिचायक होता है कि बजट को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसके छपने का काम शुरू हो चुका है। इस समारोह में बड़ी संख्या में बजट तैयार करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। दरअसल, वित्त मंत्रालय के बजट विभाग के जितने भी अधिकारी बजट बनाने के कार्य में जुटे होते हैं, उन्हें संसद में बजट पेश होने तक अपने परिवारों से संपर्क नहीं करने दिया जाता। ऐसे में सरकार उनकी मेहनत को लेकर आभार प्रकट के लिए हलवा समारोह का आयोजन करती है। हलवा सेरेमनी एक परंपरागत कार्यक्रम है जिसे बजट की छपाई से पहले मनाया जाता रहा है। कहा जाता है लंबे समय तक चलने वाली बजट बनाने की प्रक्रिया की समाप्ति के बाद मीठा खाकर बजट की छपाई को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई जाती है। वित्त मंत्री कड़ाही को हिलाती हैं और अधिकारियों को हलवा परोसकर बजट के लिए हरी झंडी दिखाई जाती है। यह समारोह वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में होता है, जहां बजट की छपाई के लिए एक विशेष प्रिंटिंग प्रेस मौजूद है। बजट तैयार करने के दौरान बरती जाती है पूरी गोपनीयता कहते हैं कि संसद में बजट पेश होने से पहले करीब 10 दिनों तक बजट से जुड़े वित्त मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में ही रहते हैं। जहां पूरी गोपनीयता रखी जाती है। दावों के मुताबिक मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की चौबीसों घंटे निगरानी रहती है, उन्हें प्रियजनों से संपर्क करने की भी अनुमति नहीं होती।

न्यूज ब्रीफ

रियलमी ने स्मार्टवॉच एस2 के साथ एआई इकोसिस्टम का किया विस्तार

नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के चलते अब वियरेबल टेक्नोलॉजी का परिदृश्य बदलाव के दौर से गुजर रहा है।वियरेबल टेक्नोलॉजी ने शुरुआत में फिटनेस ट्रैकिंग और नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स के लिए लोकप्रियता हासिल की, लेकिन जैसे-जैसे ये आम होते गए, उपभोक्ताओं की दिलचस्पी कम होती गई। अब एडवांस कैपेबिलिटी की डिमांड बढ़ी, जिसने इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए एआई की ओर प्रेरित किया। यह बिजनेस वर्ल्ड में एक बड़े ट्रेंड को दर्शाता है: एआई अब कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि टेक ब्रांड के लिए प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण घटक है। एआई वियरेबल मार्केट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके 2024 में 62.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह उछाल हेल्थ, फिटनेस और पर्सनलाइज्ड टेक्नोलॉजी में उपभोक्ताओं की बढ़ती दिलचस्पी से प्रेरित है। दूरदर्शी ब्रांड इस बदलाव को पहचान रहे हैं और उपभोक्ता की बढ़ती डिमांड को पूरा करने और मार्केट शेयर हासिल करने के लिए एआई सॉल्यूशन में निवेश कर रहे हैं। कई वियरेबल्स में वास्तविक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बजाय केवल बेसिक एल्गोरिदम शामिल होते हैं। वास्तव में आगे बढ़ने के लिए, वियरेबल्स में एआई को अपने वर्तमान फॉर्म से आगे बढ़कर इंटेलिजेंस इंटरेक्शन प्रदान करने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि सिंपल डेटा कलेक्शन और एनालिसिस से आगे बढ़कर निजी जानकारी, पूर्वानुमान क्षमताएं और हमारे जीवन के साथ सहज एकीकरण प्रदान करना। ब्रांड जो वास्तव में एआई सॉल्यूशन को सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं, वे इस तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रियलमी वियरेबल टेक्नोलॉजी में एआई एकीकरण की आवश्यकता को पहचानता है और अपने अपकमिंग रियलमी वॉच एस2 के साथ महत्वपूर्ण कदम की ओर आगे बढ़ रहा है। अपने स्मार्टफोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स (एआईओटी) प्रोडक्ट के साथ टेक इंडस्ट्री में हलचल मचाने के लिए जाने जाने वाले रियलमी का इतिहास सभी के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को सुलभ बनाने का है।

वनप्लस नोर्ड 4 फोन को लेकर जानकारी वायरल

नई दिल्ली । भारत में लॉन्च इवेंट से पहले वनप्लस नोर्ड 4 फोन को लेकर काफी जानकारियां सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। हालिया लीक से पहले एक 'एक्स' पोस्ट में इस फोन की कीमत का भी खुलासा किया था। इन लीक्स पर कपंनी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक्स अकाउंट 'वनप्लस क्लब' पर एक स्पेक्स शीट डाली गई है। यह वन प्लस नॉर्ड का आधिकारिक हैंडल नहीं है। लीक में दावा किया गया है कि वनप्लस नोर्ड 4 में 6.74-इंच यू8 प्लस ओलेड डिस्प्ले हो सकता है जिसमें 120 एचझेड रिफ्रेश रेट और 2,150 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। यह क्वालकॉम स्नैपड्रेगन 7 प्लस जेन 3 प्रोसेसर द्वारा संचालित हो सकता है, जिसमें एलपीडीडीआर5एक्स रैम और यूएफएस 4.0 स्टोरेज हो सकता है। फोन एंड्रायड 14 पर चल सकता है। नोर्ड 4 में 50-मेगापिक्सल का मुख्य सोनी सेंसर कैमरा हो सकता है जिसमें ओआईएस सपोर्ट मिल सकता है। एक 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड रियर कैमरा इसमें लगा हो सकता है और सेल्फी के लिए 16-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया जा सकता है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बनेगा सोलर पार्क, एक लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी बिजली

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के करीब 1,700 हेक्टेयर में सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) की देखरेख में बीओओ (बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट) मॉडल पर विकसित किया जाएगा। पिछले साल अगस्त में यूपीडा की ओर से प्री-फिजिबिलिटी के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया गया था, जिसमें नौ संस्थाओं की ओर से प्रेजेंटेशन दिया गया था। इनमें से मेसर्स ग्लोबल एनर्जी एलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट ने इसी साल फरवरी में अपनी विस्तृत रिपोर्ट यूपीडा के अधिकारियों के सामने पेश की थी, जिसे हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष यूपीडा के अधिकारियों ने प्रस्तुत किया था। मुख्यमंत्री योगी पूरे क्षेत्र को सोलर फार्म के रूप में स्थापित करके इसे सोलर एक्सप्रेसवे बनाना चाहते हैं।

आम आदमी पर महंगाई की मार जारी, क्यों बढ़ रही खाने-पीने की चीजों की कीमतें

नई दिल्ली ।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जून में थोक महंगाई दर बढ़ गई है। 3.36 फीसदी पर पहुंच गई है। थोक महंगाई को कहते हैं, माने होलसेल प्राइस इंडेक्स। पिछले चार महीनों से लगातार इजाफा हो रहा है।

इस स्टोरी में हम आपको महंगाई की असली तस्वीर तो दिखाएंगे ही, साथ में ये भी बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई का आप पर कितना असर होता है, या कितना असर हो सकता है एक अप्रैल 2024 भारतीय वित्त वर्ष का पहला दिन। अरहर की दाल का औसत रेट 149.23 रुपए था। चीनी 44.44 रुपए की एक किलो थी। सरसों का एक लीटर तेल 135.67 रुपए का था, आलू 24.76 रुपए किलो थे, प्याज 32.38 रुपए और टमाटर 32.97 रुपए किलो थे. ये जो दाम आपने सुने हैं ये औसत दाम थे। ये आंकडे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए हैं। अब इसी वेबसाइट पर 15 जुलाई के औसत दामों पर नजर डालते हैं. अरहर की दाल 168.75 पर पहुंच गई है, चीनी 45.03 पर, सरसों का तेल 140.82 पर, आलू 37.14 रुपए किलो, प्याज 44.67 रुपए किलो और टमाटर 68.52 रुपए किलो पर पहुंच गए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आंकडे देखने के बाद आपको महंगाई दिख भी रही होगी और महसूस भी हो रही होगी और ये तो एक बानगी मात्र है। इसी वेबसाइट पर और भी कई चीजों के दाम दिए गए हैं। अब इसके आगे की बात जानिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भी कुछ आंकड़े जारी किए हैं। इनके मुताबिक जून में थोक महंगाई दर बढ़ गई है। 3.36 फीसदी पर पहुंच गई है। थोक महंगाई को कहते हैं, माने होलसेल प्राइस इंडेक्स। पिछले चार महीनों से लगातार इजाफा हो रहा है।

मार्च में ये 0.53 फसदी थी। अप्रैल में ये 1.26 फीसदी थी, मई में 2.61 फीसदी और अब जून में 3.36 फीसदी। अब सवाल ये कि थोक महंगाई क्यों बढ़ रही है और जवाब ये कि खाने-पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। सरकारी आकंडे तस्दीक करते हैं कि आलू से लेकर प्याज तक और टमाटर से लेकर तमाम सब्जियां महंगी हो गई हैं। तमाम दालें महंगी हो गई हैं। थोक महंगाई के बाद बात करते हैं रिटेल महंगाई की। 12 जुलाई को रिटेल महंगाई के आंकड़े आए थे। जून के महीने में रिटेल महंगाई भी बढ़ गई। 5.08 प्रतिशत पर पहुंच गई। अप्रैल में ये आंकडा 4.85 प्रतिशत का था। और मई में रिटेल महंगाई 4.75 प्रतिशत पर थी। रिपोर्ट बताती है कि खाने-पीने की चीजें महंगी होने की वजह से रिटेल महंगाई बढ़ गई है। खाद्य महंगाई दर 8.69 से बढ़कर 9.36 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यही नहीं शहरी महंगाई के साथ-साथ ग्रामीण महंगाई भी बढ़ती जा रही है। रिटेल महंगाई हो या फिर थोक महंगाई। दोनों में एक चीज कॉमन है। दोनों रिपोर्ट एक बात पर मुहर लगाती हैं। वो ये कि खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। खाने-पीने की चीजें महंगी हो रही हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि कोई चीज महंगी क्यों होती है और सस्ती कब हो जाती है. दरअसल महंगाई का पूरा गणित काम करता है मांग और सप्लाई के फॉर्मूले पर। अगर किसी चीज की मांग बहुत अधिक है और सप्लाई कम है तो उस चीज के दाम बढ़ जाएंगे। वहीं अगर किसी चीज की सप्लाई अधिक है और मांग बहुत ज्यादा नहीं है तो ऐसे में उस चीज के दाम कम हो जाएंगे। यानी सब्जियों और दालों की मांग तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है। और यही कारण है कि इन चीजों के दामों में उछाल आ गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि सब्जियों और दालों की सप्लाई प्रभावित हो गई एक बड़ी वजह है उत्पादन में कमी आना। लेकिन उत्पादन में कमी क्यों आई है। दरअसल पिछले काफी वक्त से मौसम ने किसानों का साथ कम दिया है। दालों और अनाजों पर मौसम का असर हुआ है। पिछले करीब एक साल से देश में अलनीनो की स्थिति रही थी। और अब लगातार हो रही बारिश ने भी उत्पादन पर असर डाला है। यही हाल कमोबेश सब्जियों का भी है। सब्जियों का उत्पादन भी काफी प्रभावित हुआ है। इसके बाद बारी आती है सप्लाई की। सप्लाई भी प्रभावित हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है मानसून। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की खबरें रोजाना सामने आ रही हैं। देश का एक बड़ा इलाका बारिश और बाढ़ की चपेट में है। सड़कें और पुल टूटने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जलभराव और जलजमाव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में खाने-पीने की चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना परेशानी वाला काम हो गया है। सड़कों पर, हाइवे पर, खाने-पीने से लदे ट्रकों को लाना-ले-जाना खासा परेशानी भरा हो गया है। बारिश की वजह से जाम की स्थिति भी पैदा होती हैं। इस वजह से पेट्रोल-डीजल की खपत ज्यादा होती है। यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। यानी सप्लाई बिगड़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है, और इसका असर हो रहा है आपकी और हमारी जेब पर। एक और बात अगर पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो भी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं और इसके कम होने पर दामों में नरमी आ जाती है। जब बात चल ही रही है तो आपको बता दूं कि 15 जुलाई को ही पाकिस्तान सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है इसके मुताबिक वहां पर पेट्रोल के रेट 275 रुपए लीटर और हाई स्पीड डीजल के रेट 283 रुपए लीटर हो गए हैं। अब हो सकता है कि बहुत जल्द आपको एक बार फिर पाकिस्तान से आटे की लूट वाले वीडियो देखने को मिल जाएं। अब जब महंगाई से अपना हाल बेहाल है तो शायद बदहाल पाकिस्तान को देखकर कुछ सुकून मिले। महंगाई के आंकड़े जब बदलेंगे, तब फिर से आपको बताएंगे।

एप्पल ने 8 बिलियन डॉलर की मजबूत बिक्री को छुआ, इस तेजी ने चीन और वियतनाम जैसे देशों को कर दिया परेशान

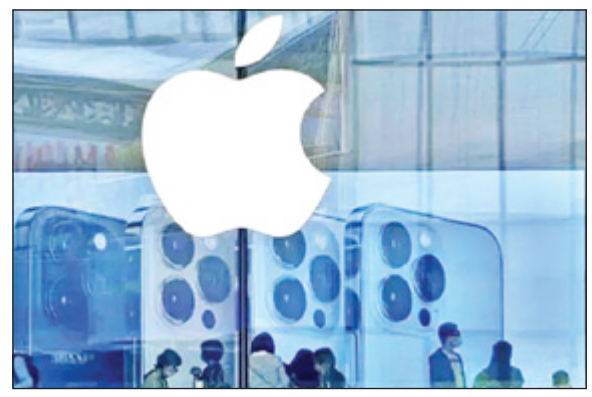

नई दिल्ली ।

टेक दिग्गज कंपनी एप्पल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत में लगभग 8 बिलियन डॉलर की मजबूत बिक्री को छुआ है, जो लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) है। भारत द्वारा उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लागू करने के कारण घरेलू विनिर्माण में आई तेजी ने चीन और वियतनाम जैसे देशों को परेशान कर दिया है। दोनों ही देश चीन और वियतनाम इस मामले में लड़खड़ा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार में प्रीमियमीकरण की सोच के कारण आईफोन की बिक्री में तेजी आई है। न केवल बेहतरीन घरेलू बिक्री, क्यूपर्टिनो बेस्ड कंपनी ने निर्यात में भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। घरेलू विनिर्माण को मिल रहे शानदार समर्थन और मजबूत वितरण के कारण इस साल आईफोन शिपमेंट में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने का अनुमान है।

काउंटरप्वाइंट रिसर्च के अनुसंधान निदेशक तरुण पाठक ने बताया कि प्रीमियमाइज़ेशन के शुरू होने के साथ ही एप्पल को एक बार फिर अपने उपकरणों और निवेश प्रस्तावों के माध्यम से इसका लाभ उठाने का सही समय मिल गया है। इसके अतिरिक्त, ब्रांड मजबूत हुआ है और कंपनी इसका भी आनंद ले रही है और देश में अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है, जिससे इसे बढ़ने में मदद मिल रही है। भारत द्वारा पीएलआई योजना को बढ़ावा देने के कारण मोबाइल फोन निर्यात में वित्त वर्ष 2024 में काफी वृद्धि हुई। इसकी वजह से चीन और वियतनाम जैसे मोबाइल बनाने वाले दिग्गज देश भारत से पीछे रह गए। चीन से मोबाइल फोन का निर्यात वित्त वर्ष 2023 में 136.3 बिलियन डॉलर से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 132.5 बिलियन डॉलर हो गया। इसी तरह, नवीनतम उद्योग आंकड़ों के अनुसार, वियतनाम में वित्त वर्ष 2023 में 31.9 बिलियन डॉलर से घटकर पिछले वित्तीय वर्ष 2024 में 26.27 बिलियन डॉलर हो गया। उद्योग के अनुमान के अनुसार, मोबाइल फोन का उत्पादन 2014-15 में 18,900 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में अनुमानित 4.10 लाख करोड़ रुपये हो गया।

आईएमएफ ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान 20 आधार अंक बढ़ाकर सात फीसदी किया, आंकड़े जारी कर कही यह बात

नई दिल्ली ।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने नया वैश्विक आर्थिक आउटलुक अपडेट जारी किया है। इस अपडेट में आईएमएफ ने उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपने विकास दर के अनुमानों को संशोधित करते हुए बढ़ा दिया है। अनुमानों में वृद्धि का कारण एशिया में मजबूत आर्थिक गतिविधियों को बताया गया है। आईएमएफ के अपडेट में भारत में विकास के पूर्वानुमान को इस वर्ष के लिए ऊपर की ओर संशोधित कर 7.0 प्रतिशत कर दिया गया है। आईएमएफ ने भारत की वृद्धि दर के अनुमान में 20 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। आईएमएफ के अपडेट में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निजी खपत के लिए बेहतर संभावनाओं की बात कही गई है। अपडेट के अनुसार 2023 में भारत की वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही। 2024 के लिए भारत के वृद्धि दर के अनुमानों में इजाफा करते हुए इसे 7.0 कर दिया गया है। 2025 में भारत के लिए वृद्धि दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत रखा गया है।

आईएमएफ के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत तक धीमी हो सकती है। अप्रैल में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में भी यही अनुमान जताया गया था। डब्ल्यूईओ को दिए अपडेट में आईएमएफ ने कहा, भारत में वृद्धि के पूर्वानुमान को भी इस साल संशोधित कर 7.0 प्रतिशत कर दिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार, विस्तार 8.2 प्रतिशत रहा, 7 प्रतिशत से अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि अर्थव्यवस्था में 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले महीने कहा था कि भारत अपने विकास प्रक्षेपवक्र में एक प्रमुख संरचनात्मक बदलाव की दहलीज पर है।

अब कैलिफोर्निया में नहीं रहेंगे स्पेसएक्स और एक्स के मुख्यालय इस कानून से नाराज होकर मस्क ने उठाया बड़ा कदम

कैलिफोर्निया ।

दिग्गज अरबपति कारोबारी एलन मस्क आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। अब वह अपनी दो कंपनी स्पेसएक्स और एक्स को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल, उन्होंने अपनी इन दोनों कंपनियों के मुख्यालय को कैलिफोर्निया से हटाकर टेक्सास ले जाने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर दी। इन शहरों में होगा एक्स और स्पेसएक्स का मुख्यालय एलन मस्क ने स्पेसएक्स के मुख्यालय और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को कैलिफोर्निया से टेक्सास स्थानांतरित करने का एलान किया। उन्होंने बताया कि स्पेसएक्स का मुख्यालय फिलहाल कैलिफोर्निया के हॉथोर्न में बना हुआ है। इसे अब टेक्सास के स्टारबेस में स्थापित किया जाएगा। वहीं एक्स का मुख्यालय अब सैन फ्रांसिस्को में नहीं रहेगा। उसे यहां से हटाकर ऑस्टिन ले जाया जाएगा। मस्क के अनुसार, इस फैसले के पीछे का कारण कैलिफोर्निया में हाल ही में पारित किया गया कानून

था, जिस पर गवर्नर गेविन न्यूजॉम ने हस्ताक्षर किया था। क्या है नया कानून इस कानून के मुताबिक, स्कूल के नियमों के तहत अब शिक्षक और स्टाफ बच्चे की लैंगिक पहचान और लैंगिक पसंद को लेकर माता-पिता समेत किसी को भी बिना बच्चे की मर्जी के नहीं बता सकते। कानून के समर्थकों का कहना है कि यह उन एलजीबीटीक्यू छात्रों की सुरक्षा में मदद करेगा जो ऐसे घरों में रहते हैं, जहां उनका सम्मान नहीं होता है। मगर विरोधियों का कहना है कि यह स्कूलों की माता-पिता के साथ अधिक पारदर्शी होने की क्षमता में बाधा पैदा करेगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूर मस्क ने कहा कि इस कानून और इससे पहले आए कई अन्य कानूनों के कारण स्पेसएक्स अब अपना मुख्यालय हॉथोर्न से स्टारबेस में स्थानांतरित करेगा। उन्होंने आगे कहा, मैंने करीब एक साल पहले गवर्नर न्यूजॉम को यह स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह के कानून परिवारों और कंपनियों को अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कैलिफोर्निया छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए ही एक्स का मुख्यालय ऑस्टिन में ले जाया जाएगा। पहले भी कर चुके हैं बदलाव गौरतलब है, यह पहली बार नहीं है, जब एलन मस्क ने अपनी किसी कंपनी को कैलिफोर्निया से बाहर ले जाने का फैसला किया है। साल 2021 में टेस्ला ने अपने कॉर्पोरेट मुख्यालय को कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो से हटाकर टेक्सास के ऑस्टिन में स्थानांतरित कर दिया था। इसके अलावा, मस्क ने अपना घर कैलिफोर्निया से हटाकर टेक्सास में बना लिया था।

कन्नड़ों को निजी कंपनियों में आरक्षण देने वाले विधेयक पर विवाद, उद्योगपतियों ने भेदभाव करार दिया

बंगलूरू ।

कर्नाटक कैबिनेट ने एक विधेयक को मंजूरी दी। इस विधेयक में निजी क्षेत्र में प्रबंधन की 50 प्रतिशत नौकरियां और गैर-प्रबंधन की 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। वहीं, निजी कंपनियों में समूह-सी और डी के पदों के लिए स्थानीय लोगों को शत प्रतिशत आरक्षण देने भी मांग की गई है। टेक उद्योग को हो सकता नुकसान राज्य के कई उद्योगपतियों ने इस विधेयक का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह भेदभावपूर्ण है और आशंका जताई कि टेक उद्योग को नुकसान हो सकता है। मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के अध्यक्ष मोहनदास पई ने कहा कि विधेयक फासीवादी और असंवैधानिक है। यह भेदभावपूर्ण और संविधान के खिलाफ उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि इस विधेयक को रद्द कर दिया जाना चाहिए। यह भेदभावपूर्ण और संविधान के

खिलाफ है। साथ ही पई ने कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश को टैग करते हुए पूछा कि क्या सरकार को यह सिद्ध करना है कि हम कौन हैं यह एनिमल फार्म जैसा फासीवादी बिल है। हम सोच भी नहीं सकते कि कांग्रेस इस तरह का विधेयक लेकर आ सकती है। क्या एक सरकारी अधिकारी निजी क्षेत्र की भर्ती समितियों में बैठेगा लोगों को भाषा की परीक्षा देनी होगी कुशल भर्ती के लिए छूट होना जरूरी इसके अलावा, बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार ने कहा कि राज्य को इस विधेयक के कारण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति पर असर नहीं पड़ने देना चाहिए और कुशल भर्ती के लिए छूट होनी चाहिए। मजूमदार ने एक्स पर कहा, एक तकनीकी केंद्र के रूप में, हमें कुशल प्रतिभा की आवश्यकता है। जबकि हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार देना है। हमें इस कदम से प्रौद्योगिकी में अपनी अग्रणी स्थिति को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ऐसी चेतावनियां होनी चाहिए जो कुशल भर्ती को इस नीति से छूट दें। भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार नहीं किया गया विधेयक एएसएसओसीएचएएम कर्नाटक के सह-अध्यक्ष और वाईयूएलयू के सह-संस्थापक आरके मिश्रा ने कहा कि विधेयक को भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए हर निजी कंपनी में एक सरकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है, तो यह भारतीय आईटी और वैश्विक क्षमता केंद्रों को डरा देगा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार की ओर से एक और प्रतिभाशाली कदम। स्थानीय आरक्षण को अनिवार्य करें और निगरानी के लिए हर कंपनी में सरकारी अधिकारी नियुक्त करें। यह भारतीय आईटी और जीसीसी को डराएगा। सीएम ने क्या कहा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक दिन पहले ही कहा था कि कर्नाटक मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी निजी उद्योगों में 'सी और डी' श्रेणी के पदों के लिए 100 प्रतिशत कन्नडिगा (कन्नड़भाषी) लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण की देखभाल करना है।

टैरिफ बढ़ाने से एक दशक के उच्च स्तर पर पहुंचेगी प्रति ग्राहक कमाई, पूंजी रिटर्न सुधारने में मदद

नई दिल्ली । मोबाइल और डाटा टैरिफ महंगा करने से दूरसंचार कंपनियों की प्रति ग्राहक कमाई (एआरपीयू) बढ़कर एक दशक के शीर्ष पर पहुंच जाएगी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा, 2025-26 तक हर मोबाइल ग्राहक से ये कंपनियां 225-230 रुपये तक कमाई करेंगी, जो बीते वित्त वर्ष के 180 रुपये से 25 फीसदी तक ज्यादा है।क्रिसिल ने जारी रिपोर्ट में कहा, उच्च लाभप्रदता और कम पूंजी खर्च के कारण दूरसंचार कंपनियों की क्रेडिट स्थिति में भी सुधार होगा। 5जी सेवाओं की शुरुआत के बाद बढ़े हुए डाटा उपयोग से एआरपीयू को भी मदद मिलेगी। वोडाफोन, एयरटेल और जियो ने हाल में टैरिफ 25 फीसदी तक बढ़ाया है। पूंजी रिटर्न सुधारने में मिलेगी मदद टैरिफ वृद्धि से 2025-26 अंत तक दूरसंचार उद्योग को पूंजी पर रिटर्न को 11 फीसदी तक सुधारने में मदद मिलेगी। 2023-24 में यह 7.5 फीसदी था। इसी तरह, कंपनियों का निवेश 28 फीसदी से घटकर अगले वित्त वर्ष में 19 फीसदी रह जाएगा, क्योंकि अधिकांश कंपनियों ने 5जी रोलआउट को पूरा कर लिया है। प्रीपेड ग्राहकों पर दिखेगा सर्वाधिक असर रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं, सोशल मीडिया और गेमिंग एप के अधिक इस्तेमाल के कारण डाटा की अधिक खपत हो रही है।इससे ग्राहक अपने डाटा प्लान को अपग्रेड करा रहे हैं। कहा, एआरपीयू में वृद्धि धीरे-धीरे होगी। इसका पूरी तरह असर चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में दिखेगा। इस बढ़ोतरी का सर्वाधिक असर प्रीपेड ग्राहकों पर दिखेगा, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है। इसलिए, जब सारे ग्राहक अगली बार रिचार्ज कराएंगे।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल- 462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01,-03, फैक्स नं.- 0755-2553914 e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) रजिस्टर्ड नं.म.प्र./296/भोपाल/2012-2014 आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/296/2015-2017